भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 500
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

दाहोद जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क

500. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल ने दाहोद जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में 4जी नेटवर्क शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दाहोद में मोबाइल नेटवर्क से वंचित गांवों की सूची तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऑनलाइन शिक्षा के उद्देश्य से दाहोद के छात्रों को बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए किसी योजना की घोषणा की गई है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) आत्मनिर्भर भारत पहल की तर्ज पर बीएसएनएल ने पूरे भारत में परिनियोजित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4जी साइट के लिए क्रय आदेश दिया है। 4जी उपकरणों की आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो गई है और दिनांक 30.06.2025 तक कुल 95,537 4जी साइट स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 90,035 साइटें ऑन-एयर हैं। बीएसएनएल गुजरात के दाहोद जिले सहित सेवा से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अपने नेटवर्क की अवसंरचना

और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 4जी सेचुरेशन परियोजना भी निष्पादित कर रहा है। वर्तमान में, दाहोद जिले के 18 आदिवासी गाँवों को बीएसएनएल 4जी सेवाओं के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ख) और (ग) दाहोद जिले के भीमपुरा और पुनाकोटा नामक दो गाँवों में 4जी कवरेज उपलब्ध नहीं है। पुनाकोटा गाँव को 4जी कवरेज के लिए चल रही 4जी सेचुरेशन परियोजना के अंतर्गत नियोजित किया गया है।

(घ) डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषित भारतनेट परियोजना (जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था) का कार्यान्वयन देश भर की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आठ राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना) में भारतनेट चरण-II को राज्य-आधारित मॉडल के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई-स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के प्रावधान सहित, सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों तक माँग के आधार पर फाइबर पहुँचाने के लिए दिनांक 04.08.2023 को 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से संशोधित भारतनेट कार्यक्रम हेतु अनुमोदन दिया गया है। बीएसएनएल इस स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढाने के लिए डिजिटल इंडिया पहलों के तहत कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/परियोजनाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा), नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) और भाषीणी आदि शामिल हैं।

*****